by the Government since the announcement of New Industrial Policy till 31-3-1994 have been approved. These involve NRI investment of about Rs. 2219.76 crores in various sectors like holel, newsprin, computer software, textiles, food processing[1], electronics, etc.

Location of NRI investment approvals is not centrally maintained.

Proposal from Pepsi-co for investment in India

7007. SHRI AHMED MOHAMED BHAI PATEL:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a proposal of PEPSI-CO Inc, US, to set up a 100 per cent holding company in India, a joint venture with Britain gas for piping gas to house hold and industrial units in greater Bombay and setting up of a wind energy part in Gujarat are among the 50 foreign investment proposals cleared by Government up-to end of February, 1994;

(b) if so, what will be the total, investment made on these projects;

(c) what are the countries and the projects that are going to be set up in India; end

(d) the total investment made by them ' in each plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) Yes, Sir. The Empowered Committee on Foreign Investment at their meeting held on 14th February, 1994 had approved 50 proposals for foreign direct investment recommended by the Foreign Investment Promotion Board. The total foreign direct investment envisaged in the projects was Rs. 617.51 crores. Details of each of the proposals approved namely name of the Indian Company. name of the foreign collaborator and (be country to which be belongs, item of manufacture and amount of foreign investment are given in the annexure. *(See* Appedix 170. Annexure No. 140).

मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए लघु उद्योग

7008. श्री गोविन्दराम सिरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय जिलेवार कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ख) इन उद्योगों में से कितने उद्योग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से संबंधित हैं और इन उद्योगों में कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इन उद्योगों के उत्पादों के विपणन के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(घ) क्या कुछ उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) के कार्य क्षेत्र में आने वाले 1,87,227 लघु एककों को 31 दिसम्बर, 1992 तक स्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया था । इन एककों के जिले-वार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं (नीचे देखिए) ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के स्वामित्व वाले उद्योगों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित वर्तमान आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं । तथापि विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा संदर्भ वर्ष 1987–88 के लिए 1989—91 के दौरान की गई लघु औद्योगिक एककों की दूसरी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार राज्य उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीकृत 76218 लघु एककों को 31 मार्च, 1988 को कार्य